

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220003 ई.मेल: cfwkum-forest-uk@nic.in

पत्र संख्या 1647 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, 24, मई, 2024।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र धिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द धिल्डियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है० वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

आपके कार्यालय की पत्र संख्या 1849/12-1 दिनांक 26.02.2024।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अपनी पत्र संख्या 2997/12-1 दिनांक 17.05.2024 से बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर से प्राप्त आख्या मय संलग्नकों सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० विजय भार्गव)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 1647 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को उनकी पत्र संख्या 2997/12-1 दिनांक 17.05.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० विजय भार्गव)

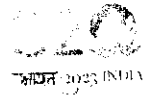
वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

संलग्नक-1



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)



dfo_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष/फैक्स नं० 05947-251362

पत्रांक 2999 / 12-1

17/05/2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

कार्यालय का संख्या/दिनांक, वन अख्य वन, उत्तराखण्ड 20-5
पंजीकरण संख्या 5737
पत्रांक संख्या 12-1
दिनांक 20-5-24

विषय:-

जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर में रानीखेत रोड के किनारे प्लॉट संख्या 08 एवं 09 में श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल पुत्र श्री महेशानन्द घिल्डियाल की (किसान सेवा केन्द्र) हेतु 0.025 है० वन भूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1849/12-1 दिनांक 28.02.2024।

सहोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गयी 3 बिन्दुओं पर सूचना निम्नानुसार आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित की जा रही है:-

1. For what provision lease was sanctioned?:- उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अवगत कराना है की सचिव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की शा०दे०सं० 1963/14-2-78/74 दिनांक 03.07.1975 से श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ रामनगर में रानीखेत मोटर मार्ग के किनारे प्लॉट सं० 08 एवं 09 की 2700 वर्गफी० वन भूमि 30 वर्षों के लिए लीज पर दिये जाने की स्वीकृति दी गयी थी। परन्तु लीजधारक द्वारा उनके पत्र दिनांक 13.03.78 के माध्यम से लीज भूमि पर पेट्रोल पम्प संचालन करने हेतु अनुमति चाही गयी। जिसके क्रम में शासनादेश संख्या 6374/14-2-578/74 दिनांक 26.06.1978 के माध्यम से सचिव, उत्तराखण्ड शासन, लखनऊ के द्वारा अनापत्ति जारी की गयी। जिसमें उल्लेख किया गया है कि:-

“यदि श्री घिल्डियाल जिलाधिकारी, नैनीताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से “नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट” प्राप्त कर लेते है तो उन्हें कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural implements workshop) के स्थापनार्थ शासनादेश संख्या 1963/14-2-78/74 दिनांक 03.07.1975 के अन्तर्गत पट्टे पर स्वीकृत भूमि में उपर्युक्त उपयोग के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।”

इस प्रकार लीजधारक का परन्तु लीज भूमि पर कृषि सेवा केन्द्र (Agricultural implements workshop) के साथ पेट्रोल पम्प खोले जाने की संरक्षक अनुमति प्रदान की गयी।

2. Is there any violation of lease deed? शा०दे०सं० 1963/14-2-78/74 दिनांक 03.07.1975 से लीजधारक श्री हरीश चन्द्र घिल्डियाल को कृषि सेवा केन्द्र के स्थापनार्थ रामनगर में रानीखेत मोटर मार्ग के किनारे प्लॉट सं० 08 एवं 09 की 2700 वर्गफी० वन भूमि 30 वर्षों के लिए लीज पर दी गयी थी। लीजधारक द्वारा उनके पत्र दिनांक 13.03.78 के माध्यम से लीज भूमि पर पेट्रोल पम्प संचालन करने हेतु अनुमति चाही गयी। जिसके क्रम में शासनादेश संख्या 6374/14-2-578/74 दिनांक 26.06.1978 के माध्यम से सचिव, उत्तराखण्ड

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

शासन, लखनऊ के द्वारा अनापत्ति जारी की गयी। वर्तमान में लीजधारक द्वारा प्रश्नगत लीज भूमि पर पेट्रोल पम्प का संचालन किया जा रहा है।

साथ ही लीजधारक द्वारा अवगत कराया गया है की भारत सरकार द्वारा बेरोजगार इंजीनियरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृषि सेवा केन्द्रों को खुलवाया गया था। परन्तु इस स्कीम के असफल होने के कारणों को जानने के लिए भारत सरकार द्वारा समिति बनाई गयी, जिसने असफलता के कारणों को देखते हुए इन्हें वीमार यूनिट मानते सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए इनके पुनर्वास की अनुशंसा की गई थी। तब भारत सरकार ने तत्कालीन लोकसभा में भी इन इंजीनियरों के पुनर्वास के लिए तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री की सहमति से प्रभावित इंजीनियरों को पेट्रो प्रोडक्ट की पेट्रोल पम्प की डीलरशिप देने आदि के लिए साक्षात्कार के द्वारा आवंटन दिया गया। (छायाप्रति संलग्न)

3. **Lease originally was granted till 2005. Why it has not been renewed after 2005?** इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखानुसार लीजधारक द्वारा लीज नवीनीकरण हेतु प्रथम आवेदन वर्ष 2008 में उनके पत्र दिनांक 22.02.2008 द्वारा किया गया था। जिसके उपरान्त उनके द्वारा पुनः पत्राचार वर्ष 2013 में किया गया, जिसके क्रम में लीजधारक को लीज नवीनीकरण प्रस्ताव गठित कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। दिनांक 05.09.2019 को प्रस्ताव आनलाईन माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात समय-समय पर विभिन्न स्तर से लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण हेतु पत्राचार अतिथि तक गतिमान है।

उपरोक्त क अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है की शा0सं0 1963/14-2-78/74 दिनांक 03.07.1975 विन्दु सं0 03 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है की-

"कृषि विलेख का आलेख्य शासन के अनुमोदनार्थ भेज दें एवं पट्टेदार को निर्देश दें कि वे 32 रू0 विधीक्षण शुल्क के रूप में निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत ट्रेजरी में जमा करके ट्रेजरी वालान गवर्नमेन्ट कन्वेन्सर, उ0प्र0 विधान भवन, लखनऊ के पास भेज दें:-

"065 अन्य सामान्य सेवायें-क-अन्य प्रशासन-1-सेवायें तथा सेवा शुल्क निजी निकायों के लिये काम करने के वास्ते सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त कीस" "

- उपरोक्त शर्तों के अवगत कराना है की लीजधारक द्वारा पट्टाविलेख तैयार नहीं किया गया है।
- उक्त लीज वर्ष 2005 तक स्वीकृत थी, जिसके नवीनीकरण हेतु लीजधारक द्वारा वर्ष 2008 में प्रथम पत्राचार किया गया। वर्तमान तक लीज नवीनीकरण नहीं हुआ है। वर्तमान में FCA 1980 के प्रविधानों के तहत उक्त लीज का नवीनीकरण नहीं हुआ है।
- उक्त लीज हेतु लीज रेंट वर्ष 2005 तक जमा किया गया है। प्रश्नगत लीज के नवीनीकरण हेतु लीज रेंट का आगणन जिलाधिकारी मैनीताल के पत्रांक 03/5-स्टाम्प/मूल्यांकन-2022-23 (संशोधित दर सूची) दिनांक 16.02.2023 (संलग्न-6) के द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर के अनुसार निम्न प्रकार किया गया है:-

- भूमि का मूल्य 1मी0 के लिए वर्तमान बाजार दर के अनुसार = रू0 47,750.00 / 1मी0²
= रू0 47,75,00,000.00 / है0
- प्रश्नगत लीज नवीनीकरण में प्रस्तावित 0.0250 है0 भूमि का मूल्य = 0.0250 X रू0 47,75,00,000.00
= रू0 1,19,37,500.00 / -
- उत्तराखण्ड शासन की शासनादेश संख्या 1125/X-3-21/02(04)/2018 दिनांक 14.09.2021 के प्रस्तर 3.14 के अनुसार प्रीमियम = जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर X लीज अवधि / 90
= रू0 1,19,37,500.00 X 30 / 90
= रू0 39,79,167.00 / -
- उत्तराखण्ड शासन की शासनादेश संख्या 1125/X-3-21/02(04)/2018 दिनांक 14.09.2021 के प्रस्तर 3.14 के अनुसार वार्षिक लीज रेंट = प्रीमियम का 3%
= रू0 1,98,958.00 / -

- उपरोक्तानुसार दिनांक 04.07.2005 से आदिधि तक 19 वर्षों का बकाय वार्षिक लीज रेन्ट = 19 वर्ष X रू0 1,98,958.00 / -
- लीज धारक द्वारा प्रश्नगत लीज नवीनीकरण के सापेक्ष वन विभाग को भुगतान किये जाने हेतु कुल धनराशि = रू0 37,80,202.00 / -
- = प्रीमियम + 19 वर्षों का बकाय वार्षिक लीज रेन्ट
- = रू0 39,79,167.00 + रू0 37,80,202.00
- = रू0 77,59,369.00

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत लीज नवीनीकरण हेतु कुल धनराशि रू0 77,59,369.00 (सतहत्तर लाख उनसठ हजार तीन सौ उनहत्तर रूपये मात्र / -) लीजधारक द्वारा भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दिगन्थ नायक)

प्रभागीय वनाधिकारी,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(दिगन्थ नायक)

प्रभागीय वनाधिकारी,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

प्रतिनिधि शासक सं० 1963/14=2=75/74 दिनांक 3=7=75 फ्रीड, मंचित
उपरोक्त शासन, लडाकू विभाग, लडाकू राज्य, पठानकोट जिल्ला

68/24

=====

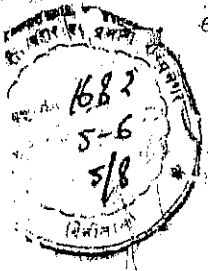
विषय :- श्री हरीश चन्द्र धारिखाल की कृषि सेवा केंद्र स्थापना
जिला नेमोलाल में उप भाूमि विभाग नामा ।

=====

उपरोक्त विभाग पर आपने पत्र सं० 2673/5=2 (र) दिनांक 3 मार्च
1975 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निवेदन हुआ है कि राज्यपाल

महोदय ने श्री हरीश चन्द्र धारिखाल की कृषि सेवा केंद्र (Agricultural
Implement Workshop) की स्थापना के सम्बन्ध में रा.ने.कोट रोड मार्ग के किनारे
2700 वर्ग फीट (प्लॉट नं० 8=1425 वर्ग फीट एवं प्लॉट नं० 9=1275 वर्ग फीट)
भाूमि निम्नलिखित शर्तों पर पट्टे पर दिये जाने के प्रस्ताव पर महामति
प्रदान कर दी है :-

1. पट्टेदार उक्त भाूमि का 7,500 रु० प्रीमियम एवं 375 रु० का फिफ्टी डिग्री का
देगा ।
2. पट्टे को अवधि 30 वर्षों की होगी ।
3. भाूमि जिस प्रयोजन के लिये दी जा रही है केवल उन्ही प्रयोजन के लिये
उपयोग में लाई जायगी । पट्टेदार की पट्टे पर स्वीकृत भाूमि को
आवश्यकता न रहने पर वह बिना कोई प्रतिज्ञा दिये ही तन में भाूमि को
वापस हो जायगी ।
4. पट्टेदार उक्त भाूमि को किसी भी भी किसी भी रूप में हस्तान्तरित
न कर सकेगा ।
5. यदि एक वर्ष के भीतर पट्टेदार द्वारा उक्त केंद्र पूर्ण रूप से स्थापित
नहीं किया जाया है तो उक्त भाूमि बिना कोई प्रतिज्ञा दिये ही शासन
द्वारा वापस ले ली जायगी ।
6. यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त कृषि सेवा केंद्र स्थापना हेतु दो वर्ष
अनुभव के भीतर ही तो आसानी से पट्टे भी उसी समय से रद्द माना
जायेगा ।
7. पट्टे को अवधि को समाप्त पर अधिकांश शर्तों के उल्लंघन के पल्लवस्य
पट्टे रद्द किये जाने पर उक्त तन भाूमि बिना कोई प्रतिज्ञा दिये ही
शासन की वापस हो जायगी एवं पट्टेदार की दो माह का समय दिया
जायेगा जिसके भीतर वे अपना समस्त सामान एवं निष्पत्ति कार्य आदि
हटाने अनुरोध उक्त समय के बाद ही भी सामान प्रशुभगत भाूमि से ले सकें



जायगा वह साधारण को संघटित ही जायगी जिसे लिये परदेदार किसे प्रतिष्ठा का हकदार न होगी ।

2. प्राप्ति धाननादि जाय. वयस्क के प्राप्ति शीर्षक " 113. वन " के गूल उप शीर्षक के अन्तर्गत जमा हो जाय ।
3. कृषि विवेका या आर्य समाज के अनुमोदनाधीन भूमि में सर्व परदेदार को निवेशा में एक ही 32 को विधोक्षण शुल्क के साथ में निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत क्षेत्रों में जमा आने वाले नालान गवर्नमेंट अन्वयेन्स, उ०प्र० विधान सदन लक्षानक के पास भूमि है :-

222

" 065-अन्य-सामान्य-वैधानिक-कानून-प्रमाण-निवेश-तथा

वेदा शुल्क निजो निवेशों के लिये काम करने के लक्ष्ये साक्षात् कार्यालयों द्वारा प्राप्ति जैस "

4. यह आर्य समाज विवेका विभाग को लक्ष्ये में निर्गत किया जा रहा है जो उनके आवासोय सं० ई - 7 = 1431/दस - 75 दिनांक 27-6-75 द्वारा प्रकृत है ।

प्रतिलिपि सूचनाधी प्रेषित ।

1. महाविद्यालय, उ०प्र० बलाहावाद ।
2. विवेका (वयस्क निवेश) अनुभाग. 7

साक्षात्,
७० सं० पो० विधानो
सचिव ।

जायलिय अति० मुख्य कार्यालय, कु० उ०प्र० नैनेताल ।

सं० न० 320/5=2 सा. (सं.) दिनांक नैनेताल जुलाई 3/ 1975

प्रतिलिपि प्रमाणोय वनाधिजाते रामनगर को उनके पत्र सं० 2500/5=4 दिनांक 7=2=1975 के संदर्भ में सूचना दी तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
साक्षात् देना के पत्र 3 पर शीर्षक कार्यवाही करें ।

अग्रोपि

सचिव

(दि० प्रमाद नशिो)
अति० मुख्य कार्यालय, कु० उ०प्र०
नैनेताल ।

सं. 1682/31/7 अति० मुख्य कार्यालय - 75

सा. प्र. 1682/31/7

प्रतिलिपि शासनादेश संख्या 6371/14-2-578/74, लखनऊ, दिनांक, जून 25, 1978 वन अनुभाग -2, प्रमुख, एनओपीओ त्रिपाठी, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में अरुणपाल, पहिचमो वृत्त, उत्तर प्रदेश, नैनोताल।

Handwritten signature/initials

विषय:- श्री हरेश नन्द थिाँडवाल को कृषि सेवा केंद्र स्थापना हेतु जिला नैनोताल में वन भूमि दिया जाना।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 6578/5-2 राठ, दिनांक

जून 16, 1978 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि यदि श्री थिाँडवाल जिलाधिकारी, नैनोताल एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से "नौ आनुवंशिक सर्वोपकरण" प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें स्थापना हेतु शासनादेश संख्या 1963/14-2-578/84, दिनांक जुलाई 3, 1975 के अन्तर्गत पट्टे पर स्वोक्त भूमि में उपर्युक्त उपयोग के साथ पैट्रोल पम्प खोले जाने में शासन को कोई आपत्ति नहीं है।

362
S-4 (घोरा नगर)
15/7 "A"

आर्.डी.ओ.
अरुणपाल

कार्यालय अरुणपाल, पहिचमो वृत्त, उत्तर-प्रदेश, नैनोताल।
पत्र संख्या 17738 / S-2(R) दिनांक: नैनोताल, जुलाई 78

प्रतिलिपि प्रभागोय वनाधिकारी सम्मन में इस कार्यालय के पत्र संख्या 6378/5-2 (राठ) का दिनांक 16-6-78 के क्रम में सूचनाएं एवं उक्त शासनादेशानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

Signature
अरुणपाल, पहिचमो वृत्त, उ.प्र.
नैनोताल।
10/7

वि/10

विषय:- पैट्रोल पम्प डिजिटल पम्प खोलने की अनुमति दिलाने हेतु।

प्रसंग:- उक्त कार्यालय श्री.एस.ए. 3843/54
दि. 14.4.78.

उपरोक्त विषय में आपकी सूचना को ध्यान में रखते हुए कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

Handwritten signature

April 4 1971

Handwritten notes:
1. [unclear]
2. [unclear]
3. [unclear]

UNITED STATES

DEPARTMENT OF

HEALTH

REHABILITATION

OF

THE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

INDEX

Page Number

1.	Name of the Scheme	:	1
2.	Objective of the Scheme	:	1
3.	Eligibility Criteria	:	1
4.	Components of the Scheme	:	
4.1	Reliefs and concessions which can be extended by banks/financial institutions to non viable Agro Service Centres which can not be Rehabilitated.	:	2
4.2	Reliefs and concessions which can be extended by banks/financial institutions to potentially viable Agro Service Centres which can be rehabilitated.	:	
4.3	Other assistance to be extended to identified sick agro service centres	:	5
5.	Implementation procedure	:	7

1. Name of the Scheme : Rehabilitation of Sick Agro Service Centres (ASCs).
2. Objective of the Scheme : The Scheme aims at rehabilitation/revival of the identified sick Agro Service Centres set up under the Centrally Sponsored Agro Service Centres Scheme which was operated through Agr. Industries Corporations at the State Level during the period 1971 to 1979 and later transferred to State sector on 1.4.79 as per decision of National Development Council.
3. Eligibility Criteria
 - 3.1: The Scheme will be confined to ASCs which were opened under the Centrally Sponsored Agro Service Centres Scheme launched in Dec., 1971 and later transferred to State Sector on 1.4.79 as per decision of National Development Council.
 - 3.2 ASCs whose owners have not migrated out of the country.
 - 3.3 The agro-entrepreneurs who have taken up alternative employment, may also be considered for assistance, provided the units are found viable and the entrepreneurs agree to run the units themselves.
 - 3.4 The agro-entrepreneurs who have sold their assets will not be considered eligible for any assistance under the scheme.
 - 3.5 Agro-Entrepreneurs who have been wilfully defunct in the past will not be eligible for assistance under the Scheme.
4. Components of the Scheme : Under the Scheme, the agro-entrepreneurs will be provided reliefs and concessions on the following pattern.
 - 4.1 Steps to be taken in the case of non-viable Agro Service Centres which are on rehabili-
 - 4.1.1 Bank will consider each case on merits and the normal steps for the recovery of bank dues will be initiated.

4.2 Reliefs and concessions which can be extended by Bank/Financial Institutions to financially viable Agric Service Centres which can be rehabilitated.

4.2.1 Penal Interest and funded interest

If penal rates of interest or charges have been charged such charges should be waived from the accounting year of the unit in which it started incurring cash losses continuously. After this is done, the unpaid interest on term loans and cash credit during this period should be segregated from the total liability and funded. If interest may be charged on funded interest, the repayment of such funded interest shall be payable in 3 years from the date of commencement of implementation of the rehabilitation programme.

4.2.2 Unadjusted interest dues

Unadjusted interest dues such as interest charged between the date upto which rehabilitation package was prepared and the date from which actually implemented, may also be funded on the same terms at 4.2.1 above.

4.2.3 Term loans

The rate of interest on term loans may be reduced, where considered necessary, by not more than three percent, the present rate, from base being less than the rate of interest charged under Integrated Rural Development Programme (IRDP).

4.2.4 Principal dues

After the unadjusted interest portion of the loan credit accounts are segregated as mentioned in 4.2.1 and 4.2.2 above, the balance representing principal dues may be

(5)

treated as irregular to the extent of its excess drawing power. This amount may be funded as Working Capital Term Loan (WCTL) with a repayable schedule not exceeding 5 years. Interest may be charged on this funded loan at 10 percent per annum.

4.2.5 Cash Losses

Cash losses are likely to be incurred in the initial stages of the rehabilitation programme till the unit reaches the break even level. Such cash losses excluding interest as may be incurred during the aursine programme may also be financed by the bank or the financial institution, if only one of them is the financier. But if both are involved in the rehabilitation package, the financial institution concerned should finance such cash losses. Interest may be charged on the funded amount at the rates prescribed by IDBI under its scheme for rehabilitation assistance.

4.2.6 Working Capital

Non-based working capital should be sanctioned to the unit to enable it to carry on its operations, with interest at the minimum of the band of the prescribed interest rates during the rehabilitation period. Where the minimum of the band exceeds 15% (as for instance in the case of working capital assistance in excess of Rs.25 lakhs, where it is 16.5%), the rate may be fixed at 15% per annum.

4.2.7 Contingency loan assistance

For meeting fluctuations in capital expenditure to be incurred during the rehabilitation programme, financial institutions may provide, where considered necessary, appropriate additional financial assistance upto 15% of the estimated cost of rehabilitation by way of contingency loan assistance. Interest on this contingency assistance may be charged at the concessional rate allowed for working capital assistance.

4.2.8. Facility for start-up expenses and working capital

There may be a need to provide the unit with funds for start-up expenses (including payment of pressing capital charges).

(6)

:- 4 -:

money for working capital in the form of long-term loans. Where a financial institution is not involved, banks may provide the loan for start-up expenses, while margin money assistance should be provided by State Government where it is operating a similar project. The rate of interest should be the same as the existing term loans.

4.3.9 Guarantee fee

The guarantee fee payable to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) in respect of sick agro-service centres should be borne by the Banks/financial institutions during the period of rehabilitation programme.

4.3 Other assistance to be extended to sick agro service centres.

4.3.1 Accommodations

State Governments will consider requirements of agro-entrepreneurs on case to case basis, for allotment of suitable accommodation at nominal charge, if such a measure has been recommended by District Level Appraisal Committee in the rehabilitation proposal of the sick agro-service centre concerned.

4.3.2 Agriculture Inputs
circulation

State Governments and State Agro-Industries Corporations will accord priority to the identified sick agro service centres in matters of giving attention for input distribution, if such measure, has been recommended by the District Level Appraisal Committee in the rehabilitation proposal of the agro service centre concerned. States may consider adopting the Maharashtra pattern in this regard. States may also designate ASCs as approved outlets for items in which cooperative do not deal in.

contd. 5/-

5.3. Pending claims of
Interest subsidy

State Governments will be requested to process and make payment of pending interest subsidy claims, if any, of the agro entrepreneurs in accordance with the provisions of the agro service centres scheme transferred to States w.e.f. 1.4.79 in pursuance to the decision of National Development Council.

Implementation
procedure.

The State AICs will be responsible for identification of eligible agro service centres as per the eligibility criteria as in para 3 above. After the approval of the rehabilitation scheme by Supreme Court of India, the Agro-Entrepreneurs shall submit their applications along with rehabilitation proposal for consideration to the concern State Agro Industries Corporation within 90 days of the order of the Supreme Court. The State Agro Industries Corporation will scrutinise the applications received, within a period of 30 days from the date of its receipt and forward the same to the District Level Appraisal Committee (DLAC).

Rehabilitation proposal as in 5.1 above will be considered by the District Level Appraisal Committee constituted as under

- (i) Distt. Collector - Chairman,
- (ii) One representative of Lead Bank. - Member
- (iii) One representative of Creditor Bank. - Member
- (iv) Representative of the Managing Director of State Agro Industries Corporation. - Secretary.

The proposals for rehabilitation considered eligible will be referred by the DLAC to the concerned bank for further details. Proposals

8

for rehabilitation not considered viable shall be rejected by the DLAC and the dues of the Bank/Financial Institution shall be recovered in such instalments as may be decided by the Bank/Financial Institution on merits of each case.

The DLAC will also review the progress of each case on quarterly basis and submit the report to the Chairman of the Task Force.

For monitoring and periodical review of the progress and removal of constraints etc, a Task Force will be set up in each of the concerned State as under:-

- i) Secretary (Agri.) : Chairman
- ii) One Representative : Member of Lending Bank
- iii) One representative : Member of Reserve Bank of India.
- iv) One representative : Member of NABARD
- v) One representative : Member of Small Industries Service Institute
- vi) Two representatives : Member of agro-entrepreneurs.
- vii) Managing Director of State Agro Industries Corporation : Member Secretary

The representative of the agro-entrepreneurs will be selected in a meeting of the agro-entrepreneurs, conducted under the Chairmanship of the Scheme of Agro Service Centres, held by the State Agro Industries Corporation under the Chairmanship of the Managing Director of the Corporation.

:-7:-

The Task Force would periodically review and monitor the progress of the scheme and submit a quarterly report to the Government of India in the Ministry of Agriculture.

5.4

5.4 A National Level Committee to review and monitor the progress of rehabilitation scheme shall be constituted. This Committee shall consist of representatives of all concerned Ministries of Government of India, RBI, IBA, all concerned Commercial Banks, State Governments, SAICs and two representatives of National Federation of Agro Entrepreneurs.

The delay in implementation of the Scheme will be reviewed by District Level Committee periodically. One of the factors contributing to such delays could be time taken for obtaining clearance to the reliefs and concessions. The banks and the financial institutions will delegate sufficient powers to senior officers at various levels such as district, divisional, regional, zonal and also at head office to sanction the banks or the financial institutions commitment to its share in the rehabilitation proposal drawn up in conformity with the Scheme approved by the Supreme Court of India and the prescribed guidelines/Instructions issued by the Reserve Bank of India from time to time.

①

UNSTARRED QUESTION NO. 1238
TO BE ANSWERED ON THE 21ST MARCH, 1982
DECLINE OF AGRO-SERVICE CENTRES

238: SHRI B. P. SINGH

Will the minister of AGRICULTURE be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that a large number of agro-service centres in the country are in a state of decline, and more than 500 such centres have been closed down, while many are on the verge of bankruptcy; and
- (b) if so, details thereof, the reasons therefor and the steps taken by Government to improve the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE

(SHRI R. V. SHANMATHAN)

(a) As per the survey conducted by the Central Govt. Training Centres at Budni and Hissar in the year 1977 covering the States of Assam, Bihar, Madhya Pradesh, J & K, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and Karnataka, 75% of the agro-service centres were operating on profit and 25% alone as not doing well. Subsequent survey carried out by the Tractor Training Centre, Hissar in 1978 revealed that 67.5% agro-service centres on an average were running on profit whereas 19.8% were working on loss. The remaining 12.7% did not report their financial benefits. As on 21st March, 1981, 508 out of 3206 centres (i.e. 15.8%) have closed down. The Government, however, have no information to lead to the conclusion that many of these centres are on the verge of bankruptcy.

(b) Details:- State-wise position of break-up of 508 centres reported to have been closed is given in annexure.

Reasons for the failure :-

As per the survey carried out in 1977 the reasons for failure of closing down of some of these centres was low work turn-over because of their being engaged only in the activity of custom hiring in tractors accompanied by competition from tractor-owning farmers, escalation in the operational cost of these machines due to hike in the prices of diesel and other lubricants and other raw materials, high cost of these machines, escalation in the cost of repair and maintenance, non-maintenance of proper records about their working, lack of requisite efforts on the part of entrepreneurs to improve their performance etc.

Steps taken by the Government to improve the situation :-

The steps taken by the Government to improve performance and financial viability of these centres are details below :-

- i) These agro-service centres were given priority allotment of tractors both indigenous and imported.
- ii) The RBI on our initiative have extended the benefits of concessional rate of interest to these agro-service centres on par with small scale industries and credit guarantee cover.

Contd. T.O.

3/2/82
H

iii) At various stages seminars and meetings were held to discuss the performance of these centres. It was advised to diversify their business on to other areas of local demands and not confine themselves to hiring of tractors alone.

iv) The Ministry of Finance advised the SBI to transfer to the nationalised banks to reimburse the States the instalments of bank loans taken by them wherever appropriate.

v) On transfer of the scheme to the States, the States were directed to honour the commitments of transfer and to extend such other necessary facilities required for running them on viable basis.

vi) Minister of State for Agriculture addressed the Ministers concerned to take such steps as would be required for strengthening these centres, including expenditure on the claims of these agro-service entrepreneurs for subsidy.

vii) Minister (A, RDR - CS) once again addressed the Ministers of the States to take action to disburse the interest charges of these entrepreneurs urgently, to route the distribution of agricultural inputs in the areas where these centres were functioning through them to help them in getting extra funding. He also advised in the various schemes implemented by the States for their welfare in their various programmes including programmes of SBI, PWD, etc. and command area development. Simultaneously he requested the Union Finance Minister to instruct the Comptroller General to waive interest charges on loans advanced to these centres and to direct the payment of principle amount. Union Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers was also addressed by him to consider the case of these centres for allotment of a special licence for petrol and petro-based lubricants.

Note:- AT THE SUPREME COURT : The Agricultural Service Centres case is not in the Parliament, but not in the Supreme Court. It is a matter to say that the Government may not submit a report to the Court. It means that our case may be posted for argument. It is a matter to the latest counter by SBI in Maharashtra. It is a matter to formidable one against us. Sri Nariman has been appointed to file such counters even in previous writ cases. It is a matter to asked for Petitioner-wise/ Writ-wise/ State-wise/ etc. So please send your latest full information.

AGRO SERVICES & FILLING CENTRE

Dealer - INDIAN OIL CORPORATION LTD.
RANIKHET ROAD, RAMNAGAR (NAINITAL) ☎ : (05945) RESI. 85523, OFF. 85484

Date 22-02-2008

No.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर ।

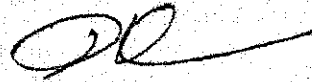
विषय:- प्लॉट संख्या 8 व 9 के लीज नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,


निवेदन इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का प्लॉट संख्या 8 व 9 का लीज नवीनीकरण होना है। अतः आप लीज नवीनीकरण करने की अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

मानचित्रकार

डिप्टी मैनजर
वन प्रभाग रामनगर


22/02

भवदीय,


(हरीश चन्द्र घिल्डियाल)
एग्रो सर्विस एण्ड फिलिंग
स्टेशन स्ट्र
रानीखेत रोड, रामनगर
(नैनीताल)

Agro Service Centre

SPONSORED BY GOVT. OF INDIA AND PATRONISED
BY U. P. STATE AGRO INDUSTRIAL CORPN. LTD.

LAKHANPUR, RAMNAGAR
NAINITAL

Date 13-3-78

Ref.

To,

The Divisional Forest Officer
Ramnagar,
Distt. Nainital

Sir,

I beg to bring to your kind notice that the Indian Oil Corporation Ltd. in pursuance of the policy of the Govt. of India to encourage and help the Agro Service centers and on the recommendation of the Managin Director, U.P. State Agro Industrial Corporation Ltd. Lucknow, has been pleased to allot a retail out let to me at Ramnagar. The retail let out is one of the importa activities of the Agro Service Centres and this out let is to be established on the land allotted to me on lease by the Forest Department at Ramnagar.

It is therefore requested to you that kindly allow me to construct the Petrol pump.

I hope that you will encourage the young entrepreneur by your kind and early favour.

Thanking you,

Yours Faithfully

(Harish Chandra Ghildyal)
(Harish Chandra Ghildyal)

N.B. The copy of appointment letter of dealership of petrol pump is attached herewith.

Services Available

CUSTOM HIRING OF :

Tractor & other
Farm Machinery

SPECIALISED IN REPAIRS OF :

Tractor, Diesel
Pump-Set and
other automobiles

SUPPLIER OF :

- * Spare Parts of Tractors
- * Trolly, Harrow and other Agricultural Implements
- * Fertilizers
- * Certified Seeds
- * Cattle & Chicken Feed
- ✓ * Diesel & Lubricant
- ✓ * Fruit Preservation Goods, Jam Jally
- * Fruit Drinks.

R/K
No. 10/7

AGRO SERVICES & FILLING CENTRE

Dealer - INDIAN OIL CORPORATION LTD.
 RANIKHET ROAD, RAMNAGAR-244715 (NAINITAL)
 ☎ : (05947) OFF.-251484, RESI.-251523



Date.....

Ref. No.

To,
 The DFO, Ramnagar
 Uttarakhand

Date: 06/08/2013

Subject: Renewal of the lease for plot no 8 & 9, on Ranikhet Road, Ramnagar, on name of Harish Chandra Ghildiyal

Dear Sir,

This is to request you to renew the lease of plot no 8 & 9 on Ranikhet Road which was allotted to Harish Chandra Ghildiyal S/o Late Shri M N Ghildiyal. This plot has office of Adarsh Cooperative transport on North, Forest compound on west and Ranikhet Road on East; since the allotment of lease, Agro Services & Filling Center (petrol pump) has been operating on this plot.

I would request you to kindly renew the lease of plot not 8 & 9 to Harish Chandra Ghildiyal to whom this plot was originally allotted.

Thanks and Regards

Harish Chandra Ghildiyal

Harish Chandra Ghildiyal
 Prop Agro Services and Filling Center
 Ranikhet Road
 Ramnagar (ntl)
 Uttarakhand

Harish Chandra Ghildiyal
 Ramnagar

06/08/2013

कार्यालय
 रामनगर
 क्र.सं. 89
 पत्रांक 12-1
 दिनांक 06/08/13

श्री हरिश् चंद्र घिल्डियाल
 ससो रामनगर उत्तरांचल
 रामनगर (नैनताल)
 निवेदन: लीडर नवीनीकरण
 कार्यका फर 6-8-2013

महोदय, आपके समक्षित पत्र की अति कृतज्ञता के साथ आपकी स्वीकृत लीडर कार्डों की निदेशित प्रकृतियों पर लीडर नवीनीकरण प्रस्ताव निमांडल का कार्यका 06/08/2013 का कार्यका है।
 कृ.सं. 89
 पत्रांक 12
 06/08/13